वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के घाटों के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं : अनुपयोज्य आस्तियों (एन०पी०ए०) के उच्च स्तर, तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादकता, लेनदेन की मात्रा को देखते हुए अपर्याप्त तकनीक और कानूनी प्रणाली के द्वारा वसूली में देरी ।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों से उनके तन्त्र और ऋण मूल्यांकन को मजबूत करने, अग्रिमों का प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने, अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित करने और उत्पादकता के स्तर में सुधार करने के लिए जोर देते रहे हैं । पूंजी पर्याप्तता आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू किया गया है। बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए सरकार ने ऋण वसूली प्राधिकरणों की स्थापना भी की है ।

(घ) और (ङ) कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचारों से भी बैंकों को हानियां होती हैं । बैंक निवारक और दण्डात्मक उपाय करते हैं ।

आयकर विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण

220. **श्री आस मोहम्मद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के सर्वेक्षण खंड ने दिल्ली के व्यापारियों, आभूषण विक्रेताओं और उद्योगपतियों द्वारा किये गये कर अपवंचन के अनेकों मामलों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) से (ग) धारा 133 क(1) के तहत किसी आयकर प्राधिकारी को उन परिसरों का सर्वेक्षण करने की अनुमति है जहां पर कोई कारोबार अथवा व्यवसाय किया जाता हो। ये सर्वेक्षण मुख्यतः छिपाई गई आय का पता लगाने के लिए किए जाते है। चालू वित्तीय वर्ष में, दिल्ली स्थित कर निर्धारण शाखा ने 234 सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणों में लगभग 11.18 करोड़ रुपये की छिपाई गई आय का पता लगाया गया है । छिपाई गई आय मुख्यतः गत वर्ष 1994–95 से संगत कर-निर्धारण वर्ष 1995–96 से संबंधित है । इन सर्वेक्षणों के अंतर्गत शामिल कर-निर्धारितियों से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की कर राशि वसूल की गई है ।

सहकारी बैंकों का पूंजी आधार

221. **श्री राघवजी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के समान सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत जहां केन्द्रीय सरकार शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करती है राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयरधारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है, कुछ सीमा तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार कर रहा है और इन योजनाओं के आधार पर उसका राज्य सरकार और राज्य तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें। इसमें अन्य बातों के साथ सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान हेतु सहायता के लिए प्रावधान किया जाएगा।

Smuggling of Brown Sugar

222. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have seized brown sugar worth Rs. 8 crores at the Indira Gandhi International Airport recently; and

(b) the steps taken/proposed to be taken by Government to check the smuggling of brown sugar in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) As per available information, the Air Customs (Preventive) staff at the Indira Gandhi International Airport seized 8 kgs of herion on 12-11-94. No precise valuation of narcotic drugs, which are often of indeterminate strength and composition and are liable for destruction, is feasible.

(b) Instructions have been issued to all enforcement agencies to maintain the utmost vigil and step up efforts under the stringent provisions contained in the NDPS Act. Training is being imparted to officers to improve their effectiveness. A part of Indo-Pak border has been fenced.

Strike by Banking Industry

223. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of strikes faced by banking industry since March, 1994 till date;

(b) the reasons therefor;

(c) the demands of the banks employees; and

(d) the action taken by Government thereon

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) There have been four All India strikes by bank employees since March 1994, viz., 8th April, 5th May, 11th May and 29th September, 1994.

(b) and (c) Reasons for resorting to strikes by the employees in banking industry were, inter alia, against alleged privatisation of banks; for grant of increment/fixed personal allowance to officers on account of computerisation and for early wage revision.

(d) IBA/Government has assured the banks' unions, time and again, that there is no move to privatise public sector banks and that their public sector character would not be compromised. They have also assued them that there is no threat to their jobs and job security. This position had also been explained personally by the Finance Minister in his meeting with the leaders of the Central Trade Unions on 29-1-1994. Further, an industry level settlement (VIth Bipartite Settlement) has been signed with the unions on 14-2-95 providing for an overall increase in wage bill to the tune of 10.5 per cent costing the banking industry Rs. 388 crores p.a. in respect of the award staff employees in the public sector banks. Discussions with officers' associations in the banking industry for wage revision are in progress